



"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का निष्पाक है और कौन कानून का निर्माता" -वेडेल फिलिपा

# दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 4 मई 2026 सोमवार

## सम्पादकीय

### चुनाव के बाद बढी महंगाई

पिछले करीब दो महीने से पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच वैश्विक स्तर पर जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उसमें रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की आपूर्ति बाधित होने के साथ ही महंगाई की रफ्तार भी तेज हुई है। ऐसे में भारत में भी महंगाई के बेलगाम होने की आशंका पहले से जताई जा रही थी। मगर ऐसा लगता है कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही सरकार ने जरूरी चीजों की कीमतों की लगाम को थाम के रखा हुआ था।

गोतलब है कि शुक्रवार को खाना पकाने के वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमत में नौ सौ तिरानबे रूपए की भारी बढ़ोतरी कर दी गई। चूकि सामान्य घरलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति बाधित है, इसलिए पांच किलो गैस वाले छोटे सिलेंडर उपलब्ध तो करार जा रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत में भी दो सौ इकसठ रूपए की बढ़ोतरी कर दी गई और अब इसके लिए उपभोक्ताओं को आठ सौ दस रूपए पचास पैसे देने होंगे। इसके अलावा, विमान ईंधन और थोक डीजल के मूल्य में भी वृद्धि की गई है। पहले को ताजा बढ़ोतरी का असर आबादी के एक छोटे हिस्से पर करने की बात कही जा रही है, लेकिन इतना तथ्य है कि इसका दायरा बड़ा होने वाला है। मसलन, केवल वाणिज्यिक गैस सिलेंडर को ही दरवासे, तो इसकी कीमत अब तीन हजार रूपए से भी ज्यादा हो गई है। जाहिर है, होटल, ढाबे या खाना पकाने का व्यवसाय करने वाले लोग अगर इसका उपयोग करेंगे, तो सीधे-सीधे। इसका असर करने—ने की चीजों की कीमतों और लोगों की थाली पर पड़ेगा। संभव है कि कम आय वाले लोगों के व्यवसाय पर भी इसका विपरीत असर पड़े।

फिर इस बात की क्या गारंटी है कि जिन कारणों से वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा करने को उचित चहारा जा रहा है, उसी तरह के दूसरे कारण से आने वाले दिनों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। आखिर छोटे सिलेंडर की कीमत में खासी बढ़ोतरी कर ही दी गई है, जिसका उद्योग आमतौर पर प्रवासी मजदूर से लेकर आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग करते हैं। इसी तरह, अब यह कहना मुश्किल है कि विमान ईंधन और थोक डीजल के मूल्यों में वृद्धि केवल यही तक रुक जाएगी। अभी से आम उपयोग वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जाने लगी है।

जाहिर है, एक ऐसा दौर शुरू हो चुका है, जिसमें महंगाई का दुरुच्छा आने वाले दिनों में और ज्यादा जटिल होना दिख रहा है। खासतौर पर डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद दुलाई का खर्ब बढ़ेगा और इसके बाद चोतरफा महंगाई की मार सबसे लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। वैश्विक स्तर पर पसरी अस्थिरता की वजह से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हाल के दिनों में जो सुरती देखी जा रही है, बचाव भी तो तब उतार-चढ़ाव से गुजर रहा है, उसमें एक बड़ी आबादी रोजी-रोजगार के सवाल से जूझ रही है। लगातार घटती क्रयशक्ति के दौर में महंगाई ही मार का असर किना गहरा हो सकता है, इसका बस अंदाजा ही लगाना जा सकता है। सवाल है कि अगर पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से उपजे संकट के बावजूद सरकार ने करीब दो महीने तक तेल और गैस की कीमतों को कम्बोडेश धम कर रखा था और इनकी उपलब्धता के वैकल्पिक रास्ते निकाल रही थी, तो अनाकल ही उसे महंगाई को इस तरह खुला छोड़ देने की जरूरत क्यों पड़ी? चुनाव कुछ दिनों की राहत का कारण पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव थे?

### नागरिक सुरक्षा के प्रश्न

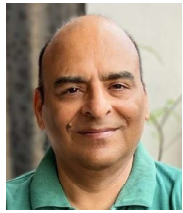
मध्य प्रदेश में जलपुर के बरगी बांध में एक क्रूज नाव के पलटने से हुए हादसे की त्रासदी ने एक बार फिर नागरिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हादसे ने नाव पर सवार होकर रोमांच महसूस करने के कई लोगों के उत्साह को मामत में बदल दिया। हैरानी इस बात की है कि दुर्घटना के बाद प्रशासन के पास नाव में सवार कुल लोगों की सटीक जानकारी तक नहीं थी। अधिकारियों ने टिकटों की संख्या के आधार पर आंकड़ा जारी कर दिया, जबकि कई लोगों के साथ उनके बच्चे भी नाव पर सवार थे।

सवाल है कि नौकाओं के संचालकों के लिए क्या यह नियम जरूरी नहीं होना चाहिए कि टिकट देने वाले लोगों के साथ उनके बच्चों की संख्या भी दर्ज की जाए, ताकि आपात स्थिति में सुरक्षा बंदोबस्त में कोई कमी न रहे? दूसरी ओर ऐसी खबरें भी आई हैं कि दुर्घटना की शिकार हुई नौका पर पहले से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे और न ही स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान की कोई व्यवस्था थी। ऐसे में इसे व्यवस्थागत लापरवाही नहीं तो और क्या कहा जाएगा।

गौरतलब है कि बरगी बांध में एक क्रूज नौका तेज आधी की चपेट में आकर पलट गई थी। इस दुर्घटना में अब तक नौ लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। जबकि कुछ लोग अब भी लापता हैं। हादसे में जीवित बचे लोगों का दावा है कि नौका पर सवार किसी भी यात्री ने जीवन रक्षक जैकेट नहीं पहनी थी। जब आपात स्थिति महसूस हुई, तभी वे यात्रियों में तितरित करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ लोगों को इन्हें पहनने का मौका ही नहीं मिला।

सवाल है कि जो नियम नौका चालकों को प्रशिक्षण के दौरान अनिवार्य रूप से सिखाए जाते हैं, अगर उन्हें ही नकारअंजक कर दिया जाए, तो यह सीधे तौर पर लापरवाही को उजागर करता है। यही नहीं, जल पर्यटन के क्षेत्र में मौसम पूर्वानुमान की व्यवस्था न होने भी सवाल खड़े करती है। राज्य सरकार ने हादसे के बाद क्रूज नावों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन क्या सिर्फ इस कदम से ऐसी दुर्घटनाओं पर पूरी तरह रोक पाएगी? ऐसे में सभी राज्यों को चाहिए कि इस हादसे से सबक लेकर तमाम व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए।

# जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा और प्रकृति



—पंकज चतुर्वेदी—

भारत में बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन एक गहरी परिस्थितिकीय समस्या को उजागर करते हैं जो मानव-निर्मित है। विकास योजनाओं और पर्यावरणीय लापरवाही ने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। भारत में मौसम का बदलता मिजाज और वैश्विक कहीं से जेट जैसी तपिश का अहसास होना अब केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि एक गहरे परिस्थितिक संकट की चेतावनी है। अक्सर भीषण गर्मी और सूखे के लिए अल नौना या वैश्विक जलवायु परिवर्तन को दोष देकर हम अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह संकट काफ़ी हद तक मानव-निर्मित है। आज हम जिस भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं, वह वैश्विक वायुमंडलीय बदलावों और स्थानीय स्तर पर पर्यावरण के प्रति बरती गई नीतिगत लापरवाही



का एक मिला-जुला परिणाम है। जब हम अपनी विकास योजनाओं के नाम पर हजारों हेक्टेयर प्राथमिक जंगलों, पहाड़ियों और जल निकायों को नष्ट करते हैं, तो हम अनजाने में उन प्राकृतिक 'कूलिंग एजेंटों' को खत्म कर देते हैं जो इस तपिश को थिराफ हमारी एकमात्र सुरक्षा थे। यूँलखड़ जैसे क्षेत्रों में, जहां तामपान अब नियमित रूप से 48 डिग्री सेल्सियस के स्तर को छूने लगा है, यह स्पष्ट है कि हमारी विकास की भूख ने धरती के प्राकृतिक धर्मोस्तर को विनाश करने के लिए प्रेरणा दी है।

इस मानव-निर्मित गर्मी की सबसे प्रत्यक्ष और क्रूर मार उन मजदूरों

और सड़क किनारे काम करने वाले श्रमिकों पर पड़ती है जो इस ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। भारत के करोड़ों निर्माण श्रमिक, रेहड़ी-पट्टरी वाले और गिग-इकोनॉमी के कर्मचारी इस गर्मी को केवल एक आंकड़े के रूप में नहीं, बल्कि एक शारीरिक हानकों के रूप में महसूस करते हैं। आंकड़ों के अनुसार, गर्मी के कारण भारत को 2030 तक अपना कुल कामकाजी घंटे का 5.8 प्रतिशत हिस्सा खोना पड़ सकता है, जो लगभग 3.4 करोड़ पूर्णकालिक नौकरियों के बराबर है। बांदा जैसे शहरों में कंटीट और कोलातार की सड़कें गर्मी को कारण गेड़ जैसी घुसल फसलों के

हैं, जिससे 'अर्बन हीट आइलैंड' प्रभाव पैदा होता है और स्थानीय तामपान ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 6 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस तक अधिक बना रहता है। नीतिगत स्तर पर मजदूरों के लिए 'छाया का अधिकार' या लू के दौरान काम के घंटों में बदलाव जैसे नियम केवल कामजो तब सीमित हैं, जो हमारे विकास के उस अंधेले को दर्शाते हैं जहां श्रम को एक जैविक इकाई के बजाय केवल एक मशीन समझा जाता है। गर्मी का यह घातक रूप हमारी खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रहा है। 'धर्मल शॉक' के कारण गेड़ जैसी घुसल फसलों के

दाने दूध भरने की अवस्था में ही सूख रहे हैं, जिससे पैदावार में 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की जा रही है। मिट्टी की नमी खत्म होने से उपजाऊ जमीन अब मरुस्थल में बदल रही है, फिर भी हमारी नीतियां सूखे क्षेत्रों में अधिक पानी चाहने वाली फसलों को बढ़ावा दे रही हैं। इसी तरह, जंगलों के विखंडन और अंधे वृक्ष नष्ट न वन्यजीवों के लिए भोजन का संकट पैदा कर दिया है। छतरपुर और पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाकों में, खून के कारण प्राकृतिक जल स्रोत सूख चुके हैं, जिससे परिणामस्वरूप जंगली जानवरों का बहिसाव हो रहा है। 40 प्रतिशत तक बढ़ गया है। यह केवल मानव-पशु संघर्ष नहीं है, बल्कि उस परिस्थितिक सुरक्षा चक्र का टूटना है जो इसी तरह और जानवरों को एक साथ पुरखित रखता था।

वर्तमान 'हीट एक्शन प्लान' (एएपीपी) की सबसे बड़ी बिकल्पता यह है कि वे केवल शहरों में मौतों को रोकने पर केंद्रित हैं, जबकि 'कारण' जल और मिट्टी के गिरते स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं। अब स्पष्ट आ गया है कि नीतिगत स्तर पर 'वह' के दुष्टिकोण को अमनाया जाए, जहां मिट्टी की नमी, पशुधन का स्वास्थ्य और वन्यजीवों का संरक्षण एक ही इकाई के रूप में देखा जाए। हमें केवल पीपारोस की रम अवधारणा से ऊपर उठकर बुदेल्खंड के चंदेलकालीन जालावों

जैसे पारंपरिक जल-प्रबंधन तंत्र को पुनर्जीवित करना होगा। ये जालाव केवल पानी का स्रोत नहीं थे, बल्कि वे स्थानीय परिस्थितिकी को ठंडा रखने के विभेदिकृत साधन थे। नीति-निर्माताओं को यह समझना होगा कि राजमार्गों के लिए काटे गए पेड़ केवल तकड़ी नहीं थे, बल्कि वे उस सूक्ष्म-जलवायु का हिस्सा थे जो फसलों को झुलसने से बचाती थी।

हमें विकास की अपनी परिभाषा को बदलना होगा। बुदेल्खंड में पत्थर खनन के लिए काटी गई हर पहाड़ी ओर उत्तराखंड में कंटीट के विस्तार के लिए नष्ट की गई हरियाली हमारे 'मिथ्या की ठंडी हवाओं' को रोक रही है। आर्थिक लाभ की तुलना में नमी के कारण होने वाला स्वास्थ्य और कृषि का नुकसान कहीं अधिक है। भविष्य की नीतियों की संकल्पना अब इस जवाबदेही पर टिकनी है कि हम बुनियादी ढांचे के निर्माण में 'ग्रीन इंजीनियरिंग' को कितना प्राथमिकता देते हैं और पर्यावरण नियमों की अनदेखी को कब बंद करते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि पर्यावरण का संरक्षण अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रिय सुरक्षा को अभिन्न हिस्सा है। तभी हम इस मानव-निर्मित हीट से बाहर निकल पाएंगे और अपने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी धरती दे पाएंगे जो केवल झुलसती नहीं, बल्कि जीवन भी प्रदान करती है।

## लोकतंत्र की सांस है आजाद मीडिया

### —बाबूलाल नागा—

हर वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को मजबूत करने का अवसर है। किसी भी देश में प्रेस की स्वतंत्रता इस बात का प्रमाण होती है कि वहां आर्थिक की कितनी आजादी है। जहां मीडिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और निष्पक्ष होता है, वहां जनता जागरूक रहती है, सरकार जवाबदेह रहती है और लोकतंत्र मजबूत होता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1993 में की थी। इसका उद्देश्य दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करना, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और स्वतंत्र पत्रकारिता के प्रति जनचेतना बढ़ाना था। आज जब सूचना का युग अपने चरम पर है, तब यह दिवस और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है।

मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। विद्यार्थी, कार्यवाहिका और न्यायपालिका के साथ-साथ प्रेस जनता और सत्ता के बीच सेतु का काम करता है। मीडिया सत्ता की नीतियों, योजनाओं और कार्यवाहिका पर नजर रखता है तथा जनता की समस्याओं को सामने लाता है। यही कारण है कि स्वतंत्र मीडिया किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है।

लेकिन आज सबसे बड़ी चिंता यह है कि विश्व सामने लाने वाले पत्रकार खुद असुरक्षित होते जा रहे हैं। दुनिया भर में पत्रकारों के 6 मासिकों दी जाती हैं, उन पर हमले होते हैं, बूटे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और कई बार उनकी हत्या तक कर दी जाती है। भारत में भी इसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कई पत्रकार शूटावर, अपराध और सत्ता के दुरुपयोग का पर्दाफास करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। यह स्थिति किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं कहे जा सकती।

पत्रकार जब किसी घोटाले, अन्याय, अपराध या जनचेतनीय नीति को खुलासा करते हैं, तब वे केवल खतर नहीं बने, बल्कि समाज को सच से परिचित कराते हैं। उनका कार्य जनता के अधिकारों की रक्षा करना है। यदि पत्रकारों को उदात्तक घुप कर दिया जाएगा, तो समाज तक सच कैसे पहुंचेगा? इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा केवल पत्रकारों का मुद्दा नहीं, बल्कि जनता के जानने के अधिकार का मुद्दा है।

आज कई बार देखा जाता है कि सरकारों की आलोचना करने वाले मीडिया संस्थाओं पर छापेमारी होती है, जांच एजेंसियों का दबाव बनाया जाता है, विज्ञापनों के जरिए आर्थिक दबाव डाला जाता है और



इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यावहारिक तरीकों में अपनाई गई एक सिफारिश के बाद की गई थी। यह अवसर प्रेस की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों को मान्यता देने और विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करने का है।

यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सामना करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है।

विश्वीय स्तरों को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए घातक है। सत्ता को आलोचना सहने की क्षमता रखनी चाहिए, क्योंकि आलोचना ही लोकतंत्र को स्वस्थ बनाती है।

भारत का सिव्दान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने है। मानविकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 19 भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकार मानता है। ऐसे में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला सीधे-सीधे नागरिक अधिकारों पर हमला है। यदि मीडिया स्वतंत्र नहीं रहेगी तो जनता तक सही सूचना नहीं पहुंचेगी और श्रम, उद तथा प्रचलन का माहौल बनाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यह संकेत देता है कि प्रेस को केवल 'लोकतंत्र' के हिंसा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पत्रकारों को कानूनी सुरक्षा, बुनियादी कार्य वातावरण और निष्पक्ष संस्थागत संरचना देना होगा। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाना चाहिए, ताकि संसदीय क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकार निराश होकर अपना कर्तव्य निभा सकें।

साथ ही मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। पत्रकारिता

## पश्चिम बंगाल के जनादेश पर टिकी निगाहें



—मनोज सिंह—

15 साल पहले बंगाल की यह वही जानता है जिसने 84: वोटिंग करके ममता बनर्जी को बंगाल की कुर्सी सीप था लेकिन एक पंचवर्षी अवधि पूरा होते-होते वहां की जनता को महसूस होने लगा कि बंगाल की सत्ता विकास से ज्यादा उब विषयों पर ध्यान देने वाली जिससे पुन: सत्ता में बन रहे यही कारण है कि प्रसिद्ध कार्यकर्ता में ही बहुत से बांदादेशी पश्चिम बंगाल में शरण लेने लगे और उनको वहां का प्रशासन रोकने में शक्ति नहीं दिखा पा रहा था क्योंकि सत्ता के शीर्ष में बैठी ममता बनर्जी आंतरिक रूप से बांदादेशी शरणार्थियों के प्रति नरम अपनाने हुए थीं ताकि वह चुनाव में अंधे—बांदादेशी सुरक्षितियों के सहारे प्रस्तावित का चीर हारण करके के सिंहासन तक पुन: काविव हो सकें और वह उसमें वह सफल भी हो गईं यही कारण है कि ममता बनर्जी के दूसरे कालक्रम में शरणार्थी पुर्णस्थितियों को सत्ता का संरक्षण मिलने लगा और उनका संख्या बल बढ़ने लगी बांदादेशी का प्रवृद्ध जनता अपने को उपेक्षित और उगा महसूस करने लगी और चुनाव के



समय वोटिंग में कम रुचि लेने लगी क्योंकि चलते दूसरे और तीसरे वोटिंग में वोटिंग प्रतिशत घटने लगा

पश्चिम बंगाल के हालात पर 29 अक्टूबर 2014 को एक लेख था कि पश्चिम बंगाल में 2014 में 52 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर बांदादेशी तय करते हैं की कि प्रायः मतदान बनेगा 100 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जिसे बांदादेशी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की स्थिति में है। यही स्थिति के अलाख से ऐसा प्रतीती हो रहा था की पुर्णस्थितियों के प्रति प्रवेश सरकार नरम रुक अपनाने हुए हैं अपने व्यक्तिगत सत्ता लाभ के लिए , क्षेत्रीय राजनीतिक दल उभरने में बने रहने के लिए विकास की जगह प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा से लिगलाह करके लगे तब वह स्थिति को विचारना पड़ता है सत्ता के खिलाफ उठ देने के लिए यही कारण है जब कई सरकार

ने पुन आई आर के माध्यम से फर्जी वोट का नाम बहुत बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल से हटाए गए और भारी संख्या में फार्स के संरक्षण होने से वहां के वोटों में बड़ी संख्या में मतदान किया गया। इस बार प्रवासी पश्चिम बंगाल की जनता ने तथा उन लोगों ने भारी संख्या में मतदान किया जो पूर्व के मतदान में क्षेत्रीय गुटों के वर्चस्व के कारण वोट नहीं डाल पा रहे थे। वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल का चुनाव संपन्न हो चुका है 4 मई को दोपहर बाद तक सभी पश्चिम बंगाल की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी राजनीतिक समीक्षाओं और चिंतन शालीनों का अनुमान है की बड़ा झुझाम प्रतिगल 15 साल बाद पुन: पश्चिम बंगाल अपना राजनीतिक इतिहास दोहराने के लिए तैयार है लोगों का अनुमान है कि इस बार भाजपा को सत्ता में आने की बहुत संभावना है कुछ लोगों का या यू कहें हमें लिगलाह अनुमान है कि भाजपा को 175 से 180 सीटें के बीच मिलने के आसार है।

## प्रोपेगंडा के रूप में सिनेमा

### —मनीष तिवारी—

1920 के दशक में चलचित्रों के आगमन से लेकर आज के ओ.टी. टी. तक, गतिशील छवि मीडिया से एक विशालाकार शिखर बनी हुई है और विश्व भर में यह तब तक सबसे शक्तिशाली जन-प्रभाव उपकरण है। एक सदी से अधिक का उदय हुआ और वे पलत की ओर गए, यही सिनेमा का पार्श्व परिवारों और युवाओं दोनों को अपने मोह में बांधे हुए है, एक साक्षा अच्युतम जो मात्र पलायनवादी से नहीं है। पहली बार, एक विश्व को बांधे वह किताब थी राजनीतिक व्यंग्य न हो, एक मानवीय चेहरा, एक उत्साहवादी संगीत और एक कथा वाप दिया जा सकता था, जो निर्देश नहीं, बल्कि जीवित अनुभव जैसा महसूस होता था। एक प्रभावकर वह सतानुवृत्ति को हथियार बना सकता था, एक मगनवद्ध वास्तविकता को मूर्त रूप देने के लिए काल्पनिक पात्रों का निर्माण कर सकता था, जिससे एक अमूर्त विश्वास्तर एक सहज सन्वादी



की तरह महसूस हो। जब अन्तर तकनीकी नवाचारों की खोज की जा रही थी, तब एल्बेक हिल्टनर और जर्नो प्रोपेगंडा मंत्री जोसेफ ग्राएबल्ट, उन पहले लोगों में से थे, जिन्होंने वास्तव में यह समझा कि फिल्म केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि रस के लिए एक केंद्रीय तंत्रिका है। नाली रोम मिनिस्ट्री को प्रतिरक्षक एनलाइटनेमेंट एंड प्रोपेगंडा के भीतर एक समकाम फिल्म विभाग-रीच वॉर ऑफ़ फ़िल्म, जिसे जीवित में आर.एफ.के. कहा जाता है, की स्थापना ने यह माना कि एक राष्ट्रवादी विचार, जिसे सिनेमा की भावनात्मक श्रवता में प्रस्तुत किया जाना है, यह तार्किक आलोचना को दरकिनार करके सीधे जनता की आत्मा में स्थापित हो सकता है।



